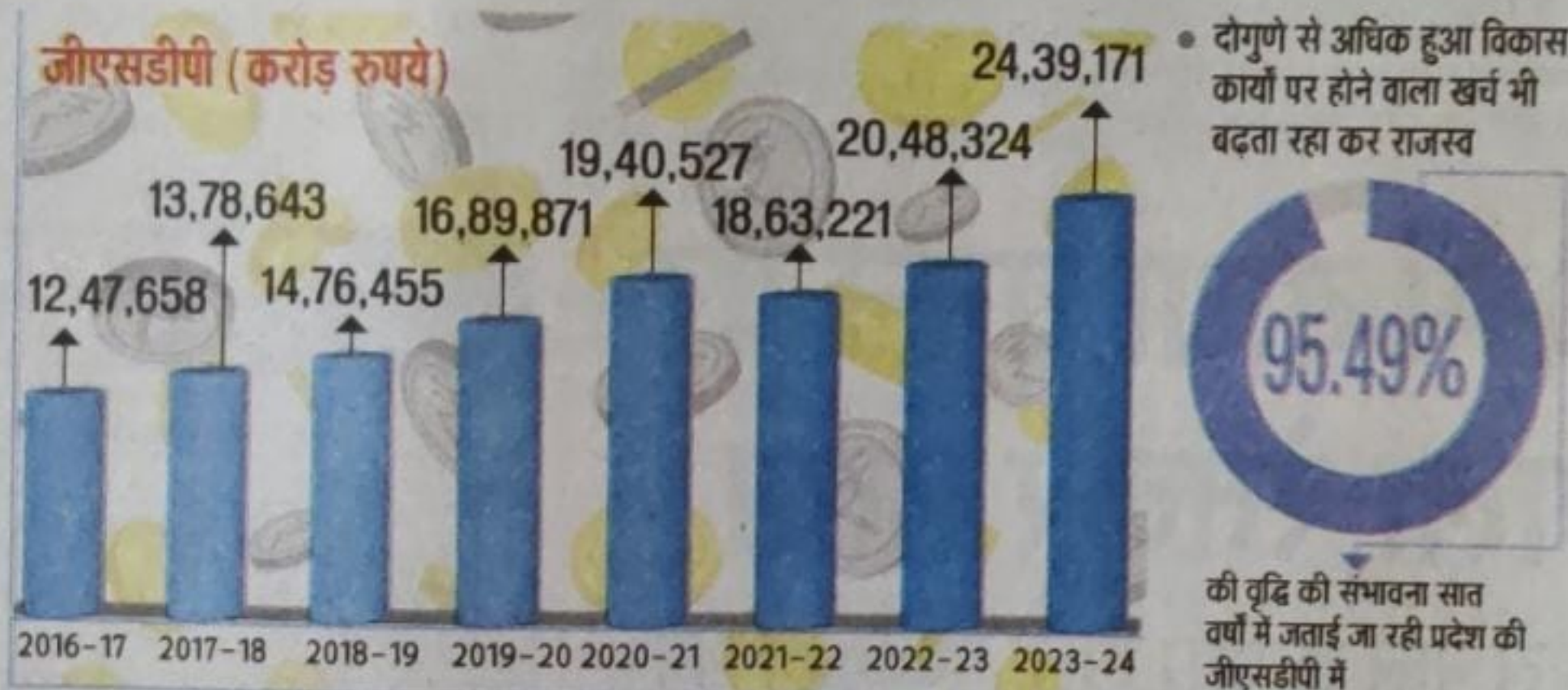


सात साल में दोगुणी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बीते सात वर्षों में न सिर्फ प्रदेश के बजट का आकार दोगुणा हुआ है, बल्कि इस अवधि में उप्र की अर्थव्यवस्था का आकार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद/ जीएसडीपी) भी लगभग दोगुणा होने के आसार हैं। वर्ष 2016-17 में प्रदेश का जीएसडीपी 12,47,658 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 24,39,171 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। इन सात वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी में 95.49 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।

विधानमंडल में बुधवार को योगी सरकार की ओर से पेश किए गए वर्ष 2023-24 के बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि वर्तमान की तुलना



में अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जीएसडीपी में 19.08 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीएसडीपी 20,48,234

करोड़ रुपये आंकी गई है। साल दर साल बढ़ने वाले बजट को ईंधन देने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं के कर राजस्व में भी वृद्धि की है।

वर्ष 2016-17 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व लगभग 86 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में 71 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 1.47

लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमानों में राज्य सरकार को स्वयं के कर राजस्व से 1.85 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने की संभावना जताई गई है। बजट के आकार के साथ राज्य के पूंजीगत परिव्यय का आकार भी सात वर्षों में दोगुणे से ज्यादा हुआ है। पूंजीगत परिव्यय से आशय परिसंपत्तियों के सृजन और नए निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च से है जिससे प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति मिलती है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय जहां 69,789.12 करोड़ रुपये था, वहीं 2023-24 में इसके बढ़कर 1,47,492.29 करोड़ होने का अनुमान है। संबंधित सामग्री » 6